

मुकदमों का विवरण

शामिल करने के लिए पहल फाउंडेशन और ए. एन. आर. v.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2017 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1224) 19 अक्टूबर, 2023

[एस. रवींद्र भाट और दीपांकर दत्ता, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:रिट याचिकाकर्ता ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013 के साथ पढ़ने के लिए निर्देश देने की मांग की।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013-कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013-पॉश अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और इसे व्यवहार्य बनाने के लिए (संबंधित शीर्षों के तहत) जारी किए गए निर्देश:

आयोजित किया गया:(ए) केंद्र सरकार और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के बीच समन्वय:प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के महिला और बाल विकास मंत्रालय को अपने प्रधान सचिव के माध्यम से विभाग के भीतर एक 'नोडल व्यक्ति' की पहचान करने पर विचार करना चाहिए, जो पॉश अधिनियम के तहत विचार किए गए समन्वय की देखरेख और सहायता कर सके-यह व्यक्ति इस अधिनियम और इसके कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार के साथ समन्वय करने में भी सक्षम होगा; (बी) सार्वजनिक प्राधिकरणों की नियुक्ति:राज्य/केंद्र शासित प्रदेश महिला और बाल मंत्रालय के संबंधित प्रधान सचिव (या कोई अन्य विभाग, नियमों के संशोधन के अधीन) व्यक्तिगत रूप से धारा 5 के तहत विचार किए गए अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रत्येक जिले में एक जिला अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे-इसके बाद, प्रत्येक नियुक्त जिला अधिकारी (ए) धारा 6 (2) के अनुपालन में ग्रामीण या आदिवासी क्षेत्र के प्रत्येक ब्लॉक, तालुका और तहसील और शहरी क्षेत्र के वार्ड या नगरपालिका में नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा; (बी) अधिनियम की धारा 6 और 7 के तहत विचार किए गए एक एल. सी. का गठन करेगा; और (सी) 676 सुनिश्चित करेगा।

675

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

इन नोडल अधिकारियों और एल. सी. के संपर्क विवरण को राज्य सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के भीतर नोडल व्यक्ति को भेजा जाएगा-इसके बाद, एक परिपत्र/बुलेटिन जिसमें

सभी जिला अधिकारियों के नाम और उनके संपर्क विवरण (फोन, पता और ईमेल) के साथ-साथ विभिन्न नोडल अधिकारियों का एक जिला वार चार्ट और उनके संपर्क विवरण को विभाग की वेबसाइट (या एक के अभाव में, मुख्य राज्य सरकार की वेबसाइट पर) पर एक विशिष्ट स्थान पर अपलोड किया जाना चाहिए, साथ ही अधिनियम, नियमों और अधिनियम की मूल बातों पर सरल चार्ट/व्याख्याकर्ताओं का एक संकलित संस्करण; (सी) नियमों में संशोधन और अंतराल जो राज्य को दर्ज करना चाहिए:केंद्र सरकार को नियमों में संशोधन करने पर विचार करना चाहिए, ताकि एक रिपोर्टिंग प्राधिकरण और/या एक वित्तीय संग्रह प्राधिकरण को मान्यता देकर अधिनियम की धारा 26 को लागू किया जा सके-केंद्र सरकार नियमों में संशोधन करने पर भी विचार कर सकती है ताकि एक विभाग (अधिमानतः महिला और बाल विभाग) की पहचान की जा सके, और उक्त विभाग के भीतर एक 'नोडल व्यक्ति' पद बनाया जा सके जो अधिनियम के कार्यान्वयन में आवश्यक समन्वय के लिए जिम्मेदार हो; (डी) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:जिला अधिकारी और एल. सी. को उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के बारे में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए-जिला स्तर पर आवधिक और नियमित प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन जिसमें जिला अधिकारी, एल. सी. के सदस्य और नोडल अधिकारी भाग लेते हैं; (ई) जागरूकता की दिशा में बड़ा प्रभाव:धारा 24 को आगे बढ़ाते हुए, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और केंद्र सरकार को इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने के लिए शैक्षिक, संचार और प्रशिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए आवंटित और या आवश्यक वित्तीय संसाधनों को निर्धारित करें और अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करें-राज्य द्वारा एक बार नामित किए जाने के बाद जिला अधिकारियों को जिले के भीतर महिलाओं और उनकी सुरक्षा के लिए काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की पहचान करने और जागरूकता पैदा करने के लिए धारा 20 (बी) के तहत अपने कर्तव्य के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है-विचाराधीन उपयुक्त सरकार या जिला अधिकारियों को एल. सी. के अस्तित्व के बारे में जागरूकता फैलाने और उन्हें असंगठित क्षेत्र के लिए सुलभ बनाने का भी प्रयास करना चाहिए।

शामिल करने के लिए पहल फाउंडेशन और ए. एन. आर. v.भारत और ओआरएस का संघ।

जो बदले में इसे अपने संबंधित एल. सी., धारा 6 (2) के तहत नियुक्त नोडल अधिकारी और अपने स्वयं के आई. सी. सी. का गठन करने वाले नियोक्ताओं को प्रसारित कर सकते हैं; (एफ) वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट:राज्य के प्रत्येक जिला अधिकारी द्वारा धारा 21 (1) और (2) और धारा 22 का उचित अनुपालन किया जाना चाहिए-राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को इस प्रक्रिया के लिए प्रक्रिया और समयसीमा सहित एक मानक संचालन प्रक्रिया (एस. ओ. पी.) बनाने का निर्देश दिया जाता है, ताकि वे अधिनियम की धारा 23 का अनुपालन कर सकें, अर्थात्, कार्यान्वयन की निगरानी और डेटा का रखरखाव; (जी) आई. सी. की निगरानी और नियोक्ताओं द्वारा अनुपालन:ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य और अन्य में पारित निर्देशों में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों (मोटे तौर पर धारा 2 (ओ) (आई) के अंतर्गत आने वाले) और कुछ निजी प्रतिष्ठानों-जैसे पेशेवर संघों को नियंत्रित करने वाले निकायों आदि में आई. सी. के गठन को सबसे विशिष्ट रूप से संबोधित किया गया है।; आई. सी. स्थापित करने और इस अधिनियम के तहत कर्तव्यों के अनुसार अनुपालन की रिपोर्ट

करने के लिए इसी तरह अस्पतालों, नर्सिंग होम, खेल संस्थानों, स्टेडियमों, खेल परिसरों, या प्रतियोगिता या खेल स्थलों (धारा 2 (ओ) (iii) और (iv) में उल्लिखित) को निर्देश दिए जाते हैं- जिला अधिकारियों को धारा 2 (ओ) के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों द्वारा संकलित) की एक सूची प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे उन्हें लिख सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि वे नियोक्ताओं से संबंधित प्रावधानों और उनके कर्तव्यों (धारा 4 के तहत आई. सी. सी. के गठन सहित, धारा 19 के तहत कर्तव्यों) के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। यह धारा 21 के तहत वार्षिक रिपोर्टों के संग्रह को भी सक्षम बनाएगा-धारा 2 (ओ) (ii) के तहत सभी निजी क्षेत्र के कार्यस्थलों को परिणामी निर्देश तब पारित किया जा सकता है जब जिला अधिकारी संस्थाओं की एक विस्तृत सूची को समझने में सक्षम हो। [पैरा 22]

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013-'हो सकता है'। 5 - चर्चा की।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013-'घरेलू कर्मचारी', 'असंगठित क्षेत्र', 'कार्यस्थल'-पर चर्चा की गई।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013-जिला कार्यालय की भूमिका-पर चर्चा की गई।

678 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

शहरों और  
अन्य संदर्भों  
की सूची

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जोगेंद्र सिंह [1964] 2 एस. सी. आर. 197-पर निर्भर था।  
ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य और अन्य (निर्णय दिनांकित)

12.05.2023 2014 के सी. ए. No.2482 में)-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

नागरिक मूल न्यायनिर्णय:2017 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1224।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

रूप:

संजय पारिख, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री सृष्टि अग्रिहोत्री, सुश्री शोभा गुप्ता, आदित्य रंजन, सुश्री जेसी कुरियन, सुश्री तरजना राय, अधिवक्ता। याचिकाकर्ताओं के लिए। लोकेश सिंहल, सीनियर ए. ए. जी., दीपक ठुकराल, सीनियर ए. ए. जी., सुश्री रेखा दयाल, सीनियर एड., सुश्री सुहसेनी सेन, सुश्री मनीषा चावा, रुस्तम सिंह चौहान, गुरमीत सिंह मक्कर, साहिल भालैक, तुषार गिरि, सिद्धार्थ अनिल

खन्ना, महफूज अहसान नाज़की, सुरजेन्दु शंकर दास, सुश्री एनी मित्तल, विनोद शर्मा, पशुपति नाथ राजदान, सुश्री मैत्रेयी जगत जोशी, आस्तिक गुप्ता, सुश्री आकांक्षा तोमर, निशे राजन शोंकर, श्रीमती अनु के. जॉय, अब्राहम मैथ्यू, आलिम अनवर, पी.

शामिल करने के लिए पहल फाउंडेशन और ए. एन. आर. v. भारत और ओआरएस का संघ।

679

एनाटोली सेमा, सुश्री लिमायिनला जमीर, अमित कुमार सिंह, सुश्री चुबालेमला चांग, प्रांग न्यूमाई, राघवेंद्र कुमार, आनंद कुमार दुबे, देवव्रत सिंह नारुका, सुश्री हर्षा शर्मा, मनीषपथक, शबरीश सुब्रमण्यम, शवोदीप रॉय, कबीर शंकर बोस, दीपायन दत्ता, विश्व पाल सिंह, सुश्री रचना गांधी, मुकेश कुमार, भरपुर सिंह, संदीप कुमार, आशीष पांडे, आकाश, गोपाल सिंह, अखिलेश्वर झा, हितेश कुमार शर्मा, नीरज सिंह, सुश्री यामिनी शर्मा, रितिका राज, सुश्री निहारिका देवीवेदी, सुश्री मंजू जेटली, गौरव अग्रवाल, सत्य मित्रा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च  
न्यायालय का  
निर्णय/आदेश

न्यायाधीश एस. रवींद्र भाट, जे.

1. रिट-याचिकाकर्ता संगठन, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत का दरवाजा खटखटाता है, जिसमें प्रतिवादियों (केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार-सामूहिक रूप से 'प्रतिवादी-राज्य' के रूप में संदर्भित) को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने के लिए उचित आदेश जारी करने की मांग की जाती है, जिसे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013 के साथ पढ़ा जाता है। विस्तृत दावे 1 शब्दशः निकाले गए हैं:

“1. अनिवार्य रूप से एक रिट या एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जो आवश्यक हो सकता है:-

ए। सभी प्रत्यर्थियों, अर्थात् भारत संघ, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम, 2013 और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, निवारण) नियम, 2013 के प्रावधानों को बिना किसी और देरी के लागू करने का निर्देश देना।

1 रिट याचिका में और साथ ही इसके बाद के इस फैसले में निम्नलिखित संक्षिप्त शब्दों का उपयोग किया गया है: “एल. सी. सी. या एल. सी. का अर्थ है 'स्थानीय समिति' (अधिनियम 23/2016 के अनुसार जिसने 'स्थानीय शिकायत समिति' को 'स्थानीय समिति' में संशोधित किया); और 'आई. सी. सी.' या 'आई. सी.' का अर्थ है 'आंतरिक शिकायत समिति'।

680 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

बी। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अधिनियम की धारा 5 के अनुसार जिला अधिकारियों को अधिसूचित करने और नियुक्त करने का निर्देश देना।

ग. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अधिनियम की धारा 6 और 7 के अनुसार सभी जिलों में एलसीसी का गठन करने का निर्देश देना।

घ. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अधिनियम की धारा 6 के अनुसार नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश देना।

ई. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अधिनियम की धारा 2 (ओ) की अवहेलना करने वाले सभी कार्यस्थलों में अधिनियम की धारा 4 के अनुसार आई. सी. सी. का गठन करने का निर्देश देना। च. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अधिनियम की धारा 21 और 22 के अनुसार संबंधित राज्यों के सभी जिला अधिकारियों द्वारा सभी कार्यस्थलों से वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट की रिपोर्टिंग और संग्रह सुनिश्चित करने का निर्देश देना। छ. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देना कि जिला कार्यालयों द्वारा एकत्र की गई वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट, जिसमें मामलों की संख्या और उनके निपटारे की जानकारी हो, को समेकित किया जाए और रिपोर्ट प्रकाशित की जाए और सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की जाए।

ज. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रामीण या आदिवासी क्षेत्र के सभी जिलों-ब्लॉक, तालुका, तहसील और शहरी क्षेत्र के वार्ड या नगरपालिका में अधिनियमों और नियमों का उचित प्रचार करने का निर्देश देना और इस अधिनियम के प्रावधानों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करना।

आई. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देना कि महत्वपूर्ण प्रावधानों का सार सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सभी कार्यस्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा।

जे. प्रत्यर्थी संख्या 1 को अधिनियम की धारा 29 में दिए गए नियमों और/या निर्देशों को तैयार करने का निर्देश देना, आई. सी. सी. और एल. सी. सी. से वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट एकत्र करने में जिलों की भूमिका को स्पष्ट करना, अधिनियम के गैर-अनुपालन के लिए एफ. आई. एन. एस. एकत्र करने में जिला अधिकारियों की भूमिका और एफ. आई. एन. एस. के संग्रह के लिए उपयुक्त प्राधिकरण;

2. जैसा कि यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, कोई अन्य रिट/आदेश/निर्देश जारी करें।”

2. कई सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय ने मामले में शामिल दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की सक्षम सहायता और सहयोग से अधिनियम, 681 के कार्यान्वयन में खामियों को स्पष्ट करने की कवायद शुरू की।

शामिल करने के लिए पहल फाउंडेशन और ए. एन. आर. v. भारत और ओआरएस का संघ। 682 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

जमीन पर। इसके अलावा, इस अदालत के आदेशों के अनुपालन में, कई राज्यों ने अधिनियम और नियमों को अक्षरशः लागू करने के लिए अपनी-अपनी सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला।

3. आई. डी. 1 पर, विद्वान वकीलों ने संबंधित केंद्रीय मंत्रालय में नोडल प्रकोष्ठों की स्थापना और देश के सभी जिलों में स्थानीय समिति की स्थापना और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में कुछ प्रश्नों पर इस अदालत को संबोधित किया। यह निर्णय इन विशिष्ट मुद्दों और इस संबंध में दिए गए सुझावों से संबंधित है। 4. हाल ही में, इस अदालत ने एक अन्य पीठ रचना में, ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य और अन्य मामले में। 3 के पास पॉश अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में निर्देश पारित करने का अवसर था। ये निर्देश उपयुक्त सरकार और उसके कई विभागों, प्राधिकरणों, संस्थानों आदि द्वारा अधिनियम के अनुपालन की मांग के संबंध में व्यापक हैं।; उच्च न्यायालय और वे न्यायालय जो इसकी देखरेख करते हैं; विशेष रूप से गैर-राज्य प्राधिकरण/संगठन जैसे-पेशेवरों के वैधानिक निकाय (शीर्ष और राज्य स्तर पर), विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल/नर्सिंग होम, आदि। इसने विशेष रूप से एन. ए. एल. एस. ए. और एस. एल. एस. ए., और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमियों को अपनी क्षमता में कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए मॉड्यूल विकसित करने का निर्देश दिया। यह देखते हुए कि पारित किए गए निर्देश वर्तमान रिट याचिका के दायरे के साथ ओवरलैप करते हैं जो इस अदालत के समक्ष है, वे जोरदार दोहराव के योग्य हैं:

“77. पी. ओ. एस. एच. अधिनियम द्वारा पूरे देश में कामकाजी महिलाओं से किए गए वादे को पूरा करने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझा जाता है:

(i) भारत संघ, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सत्यापित करने के लिए एक समयबद्ध अभ्यास करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों, सरकारी संगठनों, प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संस्थानों, निकायों आदि ने ऐसा किया है।

2 नागालैंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, गोवा, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली, कर्नाटक, मणिपुर, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात, असम, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान और निकोबार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु, केरल और त्रिपुरा शामिल हैं।

3 सिविल अपील सं. 2482/2014 में दिनांकित 12.05.2023 निर्णय।

गठित आई. सी. सी./एल. सी./आई. सी., जैसा भी मामला हो, और यह कि उक्त समितियों की संरचना सख्ती से पी. ओ. एस. एच. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है।

(ii) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आई. सी. सी./एल. सी./आई. सी. के गठन और संरचना के बारे में आवश्यक जानकारी, ई-मेल आई. डी. का विवरण और नामित व्यक्ति (ओं) के संपर्क नंबर, ऑनलाइन शिकायत जमा करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया, साथ ही संबंधित नियम,

विनियम और आंतरिक नीतियां संबंधित प्राधिकरण/कार्यात्मक/संगठन/संस्थान/निकाय की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध कराई जाएं। दी गई जानकारी को भी समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा।

(iii) इसी तरह की कवायद शीर्ष स्तर और राज्य स्तर पर पेशेवरों के सभी सांविधिक निकायों (जिनमें डॉक्टर, वकील, वास्तुकार, चार्टर्ड एकाउंटेंट, लागत लेखाकार, इंजीनियर, बैंकर और अन्य पेशेवर शामिल हैं), विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, प्रशिक्षण केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी और निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम द्वारा की जाएगी।

(iv) प्राधिकरणों/प्रबंधनों/नियोक्ताओं द्वारा आई. सी. सी./एल. सी./आई. सी. के सदस्यों को उनके कर्तव्यों और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने पर जिस तरह से जांच की जानी चाहिए, उससे परिचित कराने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

(v) प्राधिकरण/प्रबंधन/नियोक्ता नियमित रूप से आई. सी. सी./एल. सी./आई. सी. के सदस्यों को कुशल बनाने और महिला कर्मचारियों और महिला समूहों को अधिनियम, नियमों और प्रासंगिक विनियमों के प्रावधानों के बारे में शिक्षित करने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

(vi) राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए) और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) अधिनियम के प्रावधानों के साथ अधिकारियों/प्रबंधनों/नियोक्ताओं, कर्मचारियों और किशोर समूहों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मॉड्यूल विकसित करेंगे, जिन्हें उनके वार्षिक कैलेंडर में शामिल किया जाएगा।

शामिल करने के लिए पहल फाउंडेशन और ए. एन. आर. v. भारत और ओआरएस का संघ। 684 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

683

(राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमियों को अपने वार्षिक कैलेंडर, अभिविन्यास कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में स्थापित आई. सी. सी./एल. सी./आई. सी. के सदस्यों के क्षमता निर्माण और अधिनियम और नियमों के तहत जांच करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एस. ओ. पी.) का मसौदा तैयार करने के लिए शामिल करना होगा।

(viii) इस निर्णय की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को भेजी जाएगी जो संबंधित मंत्रालयों के नियंत्रण में सभी संबंधित विभागों, सांविधिक प्राधिकरणों, संस्थानों, संगठनों आदि द्वारा दिए गए निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। निर्णय की एक प्रति सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भी भेजी जाएगी जो सभी संबंधित विभागों द्वारा इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे। मंत्रालयों, भारत सरकार के सचिवों और

प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे जारी किए गए निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(ix) भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री इस निर्णय की एक प्रति निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, सदस्य सचिव, एन. ए. एल. एस. ए., अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी उच्च न्यायालयों के महापंजीयकों को भेजेगी। रजिस्ट्री इस निर्णय की एक प्रति जारी किए गए निर्देशों को लागू करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद, वास्तुकला परिषद, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान, कंपनी सचिव संस्थान और भारतीय इंजीनियरिंग परिषद को भी भेजेगी।

(x) सदस्य-सचिव, नालसा से अनुरोध है कि वे इस निर्णय की एक प्रति सभी राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिवों को प्रेषित करें। इसी तरह, राज्य उच्च न्यायालयों के महापंजीयक इस निर्णय की एक प्रति राज्य न्यायिक अकादमियों के निदेशकों और अपने-अपने राज्यों के प्रधान जिला न्यायाधीशों/जिला न्यायाधीशों को प्रेषित करेंगे।

(xi) भारतीय विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष और उपरोक्त उप-अनुच्छेद (ix) में उल्लिखित शीर्ष निकाय, बदले में, इस निर्णय की एक प्रति सभी राज्य विधिज्ञ परिषदों और राज्य स्तरीय परिषदों को, जैसा भी मामला हो, प्रेषित करेंगे।

78. भारत संघ और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अनुपालन की सूचना देने के लिए आठ सप्ताह के भीतर अपने अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। आठ सप्ताह के बाद सूची बनाएँ।”

5. इन विस्तृत निर्देशों के अलावा, वर्तमान रिट याचिका में उजागर किए गए पी. ओ. एस. एच. अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित कुछ पहलुओं पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

पॉश अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारी

6. पी. ओ. एस. एच. अधिनियम व्यापक है, और अपने आप में यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम, सजा और निवारण के लिए एक संहिता है। यह विशाखा दिशानिर्देशों में परिकल्पित उपाय को राज्य और सार्वजनिक अधिकारियों से परे किसी भी अन्य कानून की तुलना में 'कर्मचारी' 4 और 'नियोक्ता' 5 के एक बड़े, बहुत व्यापक दायरे में ले जाता है। नतीजतन, यह प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपनी चुनौतियों के साथ भी आता है। इसकी उम्मीद करते हुए, अधिनियम

4 धारा 2 (च) इस प्रकार है:

“(च) "कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कार्यस्थल पर नियमित, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर किसी भी काम के लिए प्रत्यक्ष रूप से या एक एजेंट के माध्यम से, जिसमें एक ठेकेदार भी शामिल है, मुख्य नियोक्ता के साथ या उसके बिना, चाहे पारिश्रमिक के लिए हो या नहीं, या स्वैच्छिक आधार पर या अन्यथा काम कर रहा है, चाहे रोजगार की शर्तें व्यक्त या निहित हों और इसमें एक सहकर्मी, एक अनुबंध कार्यकर्ता, परिवीक्षाधीन, प्रशिक्षु, प्रशिक्षु या ऐसे किसी अन्य नाम से बुलाया गया व्यक्ति शामिल है।

5 धारा 2 (जी) इस प्रकार है:

“(छ) "नियोक्ता" का अर्थ है -

((क) उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, प्रतिष्ठान, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या इकाई के संबंध में, उस विभाग, संगठन, उपक्रम, प्रतिष्ठान, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या इकाई का प्रमुख या उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, इस संबंध में एक आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।

((ii) उपखंड (i) के अंतर्गत नहीं आने वाले किसी भी कार्यस्थल में, कार्यस्थल के प्रबंधन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति।

स्पष्टीकरण।—इस उपखंड "प्रबंधन" के प्रयोजनों के लिए ऐसे संगठन के लिए नीतियों के निर्माण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या बोर्ड या समिति शामिल है।

((ग) उपखंड (i) और (ii) के अंतर्गत आने वाले कार्यस्थल के संबंध में, अपने कर्मचारियों के संबंध में संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने वाला व्यक्ति;

((iv) किसी निवास स्थान या घर के संबंध में, एक व्यक्ति या परिवार जो घरेलू कर्मचारी के रोजगार से कार्यरत है या लाभान्वित होता है, चाहे नियोजित ऐसे कर्मचारी की संख्या, समय अवधि या प्रकार, या घरेलू कर्मचारी द्वारा किए गए रोजगार या गतिविधियों की प्रकृति कुछ भी हो;

शामिल करने के लिए पहल फाउंडेशन और ए. एन. आर. v. भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 686

685

इसके कार्यकरण के लिए एक स्तरीय मॉडल प्रदान करता है, और बदले में इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए।

7. प्रत्येक नियोक्ता को कानूनी रूप से धारा 4 के तहत एक आई. सी. सी. का गठन करने के लिए अनिवार्य किया गया है। उन कमियों को दूर करने के लिए जहां कोई आई. सी. सी. नहीं है (यानी, उन कार्यस्थलों में काम करने वालों के लिए जो 10 से कम श्रमिकों को नियुक्त करते हैं या जहां नियोक्ता स्वयं प्रतिवादी हैं), अधिनियम प्रत्येक जिले में एक एल. सी. का प्रावधान करता है, जिसका गठन धारा 6 के तहत जिला कार्यालय द्वारा किया जाना है। जिला कार्यालय को शिकायतें प्राप्त करने और संबंधित एल. सी. 6 को अग्रेषित करने के लिए ग्रामीण या आदिवासी क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, तालुका और तहसील और शहरी क्षेत्र में वार्ड या नगरपालिका में एक नोडल अधिकारी नामित करने का भी काम सौंपा गया है। ये नोडल अधिकारी इस मायने में संपर्क का पहला बिंदु हैं, विशेष रूप से उन स्थितियों में जहां कोई आई. सी. सी. गठित नहीं है। आई. सी. सी. या एल. सी. को जांच करने के बाद (या यदि ऐसा मामला है तो समझौता 7 दर्ज करना), अपनी जांच रिपोर्ट में क्रमशः नियोक्ता या जिला कार्यालय को प्रत्येक मामले में प्रतिवादी (या शिकायतकर्ता के खिलाफ झूठे/दुर्भावनापूर्ण मामले की स्थिति में) के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, इसकी सिफारिश करनी होती है।

8. याचिकाकर्ता ने बताया है कि धारा 21 और 22 के तहत विचार की गई वार्षिक रिपोर्टों के संबंध में जिला कार्यालय की भूमिका के बारे में स्पष्टता की कमी है। इन प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से कुछ स्पष्टता आती है: आई. सी. सी. और एल. सी. दोनों वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं और इसे या तो सीधे (एल. सी. के मामले में) या नियोक्ता (यहाँ, आई. सी. सी.) के माध्यम से जिला कार्यालय में

जमा करते हैं। जबकि धारा 21 (1) में आई. सी. सी. की रिपोर्ट को जिला कार्यालय को भेजे जाने का उल्लेख नहीं है, इसके तुरंत बाद धारा 22 में कहा गया है कि नियोक्ता को अपनी रिपोर्ट में दर्ज किए गए और निपटाए गए मामलों की संख्या (यदि कोई हो) का उल्लेख करना अनिवार्य है, और रिपोर्ट के अभाव में भी उसे जिला कार्यालय को संख्या की सूचना देनी चाहिए। इसके अलावा, यह जिला अधिकारी है, जो राज्य सरकार को एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

6 पॉश अधिनियम की धारा 6 (2)। 7 पॉश अधिनियम की धारा 10।

8 पॉश अधिनियम की धारा 14 और नियमों का नियम 10। 9 पॉश अधिनियम की धारा 13 और नियमों के नियम 9। 10 पॉश अधिनियम की धारा 21 (1)।

11 पॉश अधिनियम की धारा 22। 12 पॉश अधिनियम की धारा 21 (2)।

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

9. उपयुक्त सरकार (धारा 2 (बी) के तहत), इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के सभी मामलों के संबंध में नेतृत्व और निपटारे के मामलों की संख्या पर डेटा बनाए रखने के लिए अंतिम स्तर पर जिम्मेदार है। यह अधिनियम 14 को प्रचारित करने के लिए उपाय करने के लिए भी बाध्य है। ढांचे में एक अन्य अंतर्निहित सुरक्षा यह है कि उपयुक्त सरकार को अभिलेखों की जानकारी और निरीक्षण के लिए बुलाने का अधिकार है-जिसमें वह किसी नियोक्ता या जिला अधिकारी से यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी जानकारी लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है, या निरीक्षण करने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक कोई भी रिकॉर्ड प्रस्तुत कर सकती है।

10. अधिनियम की योजना की इस रूपरेखा से जो बात पूरी तरह से स्पष्ट है, वह यह है कि जिला अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है; वे अधिनियम के कार्यान्वयन में कई पहलुओं के लिए जिम्मेदार हैं। यही वह जगह है जहाँ पॉश अधिनियम से संबंधित समन्वय और जवाबदेही के संदर्भ में पैसा रुकता है। भुगतान और शुल्क के संदर्भ में भी-जिला अधिकारी एल. सी. 16 के अध्यक्ष और सदस्यों को भत्तों के भुगतान के लिए जिम्मेदार है, जिसे वह राज्य सरकार द्वारा स्थापित एजेंसी से प्राप्त करता है (संदर्भ: अधिनियम की धारा 8)। दिलचस्प बात यह है कि जिला अधिकारी भी प्रवर्तन के संदर्भ में एक कर्तव्य का पालन करता है; धारा 13 के तहत, यदि प्रतिवादी किसी भी मामले में इस तरह से निर्देशित किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो आई. सी. सी./एल. सी. संबंधित जिला कार्यालय को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली के लिए आदेश भेज सकता है।

11. धारा 5 में कहा गया है कि:

“5. उपयुक्त सरकार जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकती है। प्रत्येक जिले को इस अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने या कार्यों का निर्वहन करने के लिए।

और अध्याय VII, जिसका शीर्षक 'जिला कार्यालय के कर्तव्य और शक्तियाँ' है, धारा 20 के तहत कहता है:

13 पॉश अधिनियम की धारा 23। 14 पॉश अधिनियम की धारा 24। 15 पॉश अधिनियम की धारा 25। 16 पी. ओ. एस. एच. नियमों का नियम 5

17 पॉश अधिनियम की धारा 13 (3) का दूसरा प्रावधान।

शामिल करने के लिए पहल फाउंडेशन और ए. एन. आर. v. भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 688

687

“20. जिला अधिकारी, -

(क) स्थानीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत करने की निगरानी करना;

(ख) यौन उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए ऐसे उपाय करना जो आवश्यक हो।”

जबकि धारा 5 में उपयोग की जाने वाली भाषा 'मई' है, कानून का संदर्भ-जैसा कि ऊपर विस्तृत किया गया है, और निर्दिष्ट रूप से धारा 20 (जो 'विल' का उपयोग करता है और जिला कार्यालय को महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए बाध्य करता है) यह स्पष्ट करता है कि जिला कार्यालय, प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, जिसे निवारण और निगरानी ढांचे को अक्षुण्ण रखने और सुचारु रूप से चलाने का काम सौंपा गया है। व्याख्या पर पहले मामलों में से एक में

'मई' के मामले में, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जोगेंद्र सिंह 18 में इस अदालत ने निर्णय दिया: “इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'मई' शब्द का आम तौर पर अर्थ 'जरूरी' या 'होगा' नहीं होता है। लेकिन यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि "हो सकता है" शब्द संदर्भ के आलोक में "जरूरी" या "होगा" का अर्थ रखने में सक्षम है। यह भी स्पष्ट है कि जहां एक सार्वजनिक प्राधिकरण को एक दायित्व के साथ एक विवेकाधिकार प्रदान किया जाता है, 'मई' शब्द जो विवेकाधिकार को दर्शाता है, उसका अर्थ एक आदेश के रूप में माना जाना चाहिए। कभी-कभी, विधायिका उस प्राधिकरण के उच्च दर्जे के सम्मान में "हो सकता है" शब्द का उपयोग करती है जिसे शक्ति और दायित्व प्रदान करने और अधिरोपित करने का इरादा है। वर्तमान मामले में यह संदर्भ निर्णायक है।”

धारा 5 को निर्देशिका के रूप में मानने से, अन्यथा स्पष्ट रूप से चित्रित कार्य और निवारण तंत्र में एक बड़ी कमी आ जाएगी, और इसके परिणामस्वरूप इस विधान की प्रभावशीलता कम हो जाएगी।

12. हमने नोटिस प्राप्त करने के बाद कई राज्यों के नेतृत्व में दिए गए जवाबों/हलफनामों का अध्ययन किया है; एक साथ देखा जाए तो वे अधिनियम के कार्यान्वयन के मामले में एकरूपता की कमी से चिह्नित हैं। कई राज्यों ने अपने मौजूदा नौकरशाही ढांचे के भीतर अधिनियम की संस्थागत आवश्यकताओं को लागू करने की कोशिश की है (उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों ने अपने महिला और बाल विभागों के अलावा अन्य विभागों को इसका कार्यान्वयन सौंपा है)।

18 [1964] एससीआर (2) 197

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

विकास मंत्रालय, जैसे समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, विधायी मामलों आदि से संबंधित विभाग।) राज्यों द्वारा दिए गए जवाबों के जवाब में याचिकाकर्ता के नेतृत्व में दायर याचिका विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पॉश अधिनियम के कार्यान्वयन में कई खामियों और एकरूपता की कमी को उजागर करती है। जिला अधिकारियों को इस रिट याचिका की सूचना दिए जाने के बाद अधिकांश राज्यों में अधिसूचित किया गया था, और यहां तक कि उन राज्यों में भी जिन्होंने कार्रवाई की है- उन्होंने अधिकारियों, उनकी संपर्क जानकारी, आदि का कोई विशिष्ट विवरण प्रदान किए बिना, जिला अधिकारियों के रूप में एक विशिष्ट पद को अधिसूचित किया है। अधिकांश राज्य एल. सी. के गठन पर प्रलेखन प्रदान करने में विफल रहे हैं, और यहां तक कि जिनके पास है, उनमें से कई ने प्रत्येक जिले में एक का गठन नहीं किया है। केवल कुछ मुट्ठी भर राज्यों ने 'नोडल अधिकारियों' का कोई विवरण प्रदान किया है-लेकिन इनमें से भी, नोडल अधिकारी निर्दिष्ट सी पद अधिसूचित हैं, न कि प्रत्येक तालुका, वार्ड, नगरपालिका आदि में व्यक्ति, जैसा कि धारा 6 (2) के तहत विचार किया गया है। वार्षिक रिपोर्टों की जानकारी शायद सबसे अधिक खतरनाक है-केवल तीन ने एक समेकित रिपोर्ट प्रदान की है (विभिन्न स्रोतों, या केवल एल. सी. पर भरोसा करते हुए)। प्रत्येक राज्य ने अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एक अलग मंत्रालय को 'नोडल' मंत्रालय के रूप में अधिसूचित किया है-कुछ ने समाज कल्याण मंत्रालय या उसके संबद्ध विभागों को अधिसूचित किया है, जबकि अन्य महिला और बाल विकास विभाग पर निर्भर हैं।

13. एफ़ी दावितों का, विशेष रूप से भारत संघ का, सामान्य जोर बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान और सलाह जारी करने, पुस्तिकाओं के प्रकाशन आदि के माध्यम से जागरूकता पैदा करने पर रहा है। हालांकि, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हालांकि जागरूकता पैदा करना आवश्यक है, अगर कोई महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न करती है-तो निवारण के लिए ढांचा वास्तव में मौजूद होना चाहिए। जिला अधिकारियों को विशेष रूप से अधिसूचित करने में विफलता, अन्य पहलुओं के अलावा, एल. सी. और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति पर एक भारी प्रभाव डालती है। शिकायत तंत्र, और बड़ा ढांचा-चाहे कितना भी प्रभावी क्यों न हो, अपर्याप्त रहता है यदि अधिनियम में निर्धारित अधिकारियों को विधिवत नियुक्त/अधिसूचित नहीं किया जाता है। इसलिए, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक जिले में, हर समय एक अधिसूचित जिला कार्यालय हो; सेवानिवृत्ति या किसी अन्य कारण से हुई रिक्ति के मामले में, इसे विधिवत

सुधार किया जाना चाहिए, ताकि अधिकारियों के बीच सुचारु रूप से संक्रमण हो सके, और यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस पद का हमेशा कोई प्रभारी हो। इसके अलावा, इन जिला अधिकारियों को उनकी भूमिकाओं और दायित्वों पर जोर देने के साथ अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के संबंध में उन्मुख करने, प्रशिक्षित करने और संवेदनशील बनाने का कार्य किया जाना चाहिए। इसी तरह की गतिविधियों की सीमा 689 होनी चाहिए।

शामिल करने के लिए पहल फाउंडेशन और ए. एन. आर. v. भारत और ओआरएस का संघ। 690 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

प्रत्येक जिला कार्यालय द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों और गठित एल. सी. के लिए संचालन किया जाएगा।

असंगठित क्षेत्र के लिए अधिनियम का संचालन

14. यह अधिनियम एक 'क्षैतिज' तंत्र और अधिकार ढांचे के साथ एक अग्रणी कानून है। कुछ परिभाषाओं पर एक नज़र- 'कर्मचारी' 19, 'नियोक्ता' 20, और 'कार्यस्थल' 21 इस बिंदु को घर ले जाते हैं और इसके क्षैतिज अनुप्रयोग के दायरे को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा, धारा 2 में 'घरेलू कामगार' और 'असंगठित क्षेत्र' की अवज्ञाओं को शामिल करना, जो हालांकि अधिनियम की मूल सामग्री में स्पष्ट रूप से संदर्भित नहीं है, बता रहा है:

“(ड) "घरेलू कर्मचारी" से ऐसी महिला अभिप्रेत है जो किसी भी घर में घरेलू काम करने के लिए पारिश्रमिक के लिए नियोजित है, चाहे वह नकद या किसी भी प्रकार का हो, या तो प्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंसी के माध्यम से अस्थायी, स्थायी, अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर, लेकिन इसमें नियोक्ता के परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं है।

“(पी) कार्यस्थल के संबंध में "असंगठित क्षेत्र" का अर्थ है व्यक्तियों या स्व-नियोजित श्रमिकों के स्वामित्व वाला और वस्तुओं के उत्पादन या बिक्री या किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करने में लगा हुआ उद्यम, और जहां उद्यम श्रमिकों को नियुक्त करता है, ऐसे श्रमिकों की संख्या दस से कम है।”

इन परिभाषाओं को शामिल करने से इस अधिनियम के लागू होने का दायरा बहुत बढ़ गया है। एक पीड़ित घरेलू कर्मचारी, इस प्रकार, एल. सी. ढांचे का उपयोग करके, जिस घर में वे काम करते हैं, वहां रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है; धारा 2 (ओ) देखें जो 'कार्यस्थल' की अवहेलना करती है और इसमें उपखंड (vi) के तहत 'एक निवास स्थान या घर' शामिल है:

“(ओ) "कार्यस्थल" में शामिल हैं -

(i) कोई भी विभाग, संगठन, उपक्रम, प्रतिष्ठान, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या इकाई जो स्थापित, स्वामित्व, नियंत्रित या पूरी तरह से या पर्याप्त रूप से उचित सरकार या सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है।

19 धारा 2 (च), एफएन 4 में ऊपर निकाली गई है। 20 एफ. एन. 5 में ऊपर निकाली गई धारा 2 (जी)। 21 अधिनियम की धारा 2 (ओ)।

स्थानीय प्राधिकारी या सरकारी कंपनी या निगम या सहकारी समिति;

((ii) कोई निजी क्षेत्र का संगठन या कोई निजी उद्यम, उपक्रम, उद्यम, संस्थान, प्रतिष्ठान, समाज, न्यास, गैर-सरकारी संगठन, इकाई या सेवा प्रदाता जो वाणिज्यिक, व्यावसायिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजन, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाओं या उत्पादन, आपूर्ति, बिक्री, वितरण या सेवा सहित वित्तीय गतिविधियों को संचालित करता है;

((ग) अस्पताल या नर्सिंग होम;

((iv) कोई भी खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल परिसर या प्रतियोगिता या खेल स्थल, चाहे वह आवासीय हो या प्रशिक्षण, खेल या उससे संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता हो;

(v) ऐसी यात्रा करने के लिए नियोक्ता द्वारा परिवहन सहित रोजगार से उत्पन्न या उसके दौरान कर्मचारी द्वारा दौरा किया गया कोई भी स्थान;

(vi) एक निवास स्थान या एक घर "

15. इसके बाद, एल. सी. की संरचना और भूमिका पर विचार करें-जो जिले में मूलभूत निकाय है, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के लिए। इस समिति की अध्यक्षता एक नामित अध्यक्ष द्वारा की जाती है जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित महिला है और महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध है; एक सदस्य को ब्लॉक/तालुका/तहसील (ग्रामीण) या वार्ड/नगरपालिका (शहरी) में काम करने वाली महिलाओं में से नामित किया जाता है; दो और, जिनमें से कम से कम एक महिला को गैर सरकारी संगठनों या महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध संघों के बीच नामित किया जाना चाहिए या यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा किसी को कानूनी पृष्ठभूमि/कानून का ज्ञान होना चाहिए, और किसी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित होना चाहिए। एल. सी. को जांच करने, समन जारी करने, उपस्थिति लागू करने आदि के लिए दीवानी अदालत 23 के बराबर शक्तियों के साथ सशक्त किया गया है, जो ढांचे में इसके महत्व को दर्शाता है। ऐसे गैर सरकारी संगठनों से नामांकित व्यक्तियों को शामिल करना भी सहायक है, क्योंकि एक ऐसे संदर्भ में जहां एल. सी. औपचारिकता की भावना व्यक्त कर सकते हैं, महिलाओं के लिए और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों से संपर्क करना आसान है।

22 अधिनियम की धारा 6 और 7 के अनुसार। 23 अधिनियम की धारा 11।

शामिल करने के लिए पहल फाउंडेशन और ए. एन. आर. v. भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 692

2015 की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई. एल. ओ.) की रिपोर्ट 24 में यह एक निष्कर्ष है। हालाँकि, जैसा कि बताया गया है, इन गैर-सरकारी संगठनों के लिए ऐसी सहमति वाली महिलाओं की ओर से मामले को पंजीकृत करने या आगे बढ़ाने के लिए कानून में कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार, एल. सी. से संबंधित जागरूकता का प्रसार और औपचारिकता की हवा को दूर करना, उच्चतम स्तर के राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए, जो अधिनियम को लागू करना चाहते हैं।

16. अंत में, अधिनियम की एक बड़ी सीमा को ध्यान में रखना प्रासंगिक है, जो राज्यों को धन वितरित करने के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर करती है, जो एक एजेंसी का उपयोग करके इसे जिला कार्यालय को हस्तांतरित कर सकती है। इसी तरह धारा 20 और 24, जो जिला अधिकारी और उपयुक्त सरकार को अधिनियम को प्रचारित करने के लिए कदम उठाने के लिए बाध्य करती है, धारा 24 द्वारा सीमित है जिसमें कहा गया है कि:

“उपयुक्त सरकार, उपलब्धता के अधीन हो सकती है

वित्तीय और अन्य संसाधन, -

(क) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने वाले इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जनता की समझ को आगे बढ़ाने के लिए प्रासंगिक जानकारी, शिक्षा, संचार और प्रशिक्षण सामग्री का विकास करना और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना; (ख) [स्थानीय समिति] के सदस्यों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना।”

(जोर दिया गया)

संबंधित अधिकारियों को भुगतान करने और जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक निर्दिष्ट बजट के अभाव में, विभिन्न एल. सी. निष्फल हो जाते हैं या खाली रहते हैं। इसलिए, केंद्र सरकार से अनुदान के वितरण का पता लगाने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर और उसके बाद राज्य स्तर पर इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए बजट निर्धारित करने की आवश्यकता है।

24 आई. एल. ओ., भारत के परिधान में काम करने की स्थितियों पर अंतर्दृष्टि (2015) // रूरल इंडिया ऑनलाइन।ओ. आर. जी./एन./पुस्तकालय/संसाधन/अंतर्दृष्टि-से-काम करने की शर्तें-इन-इंडिया-परिधान-उद्योग/> (17.10.2023 पर पहुँचा गया)।

25 अधिनियम की धारा 8।

26 अधिनियम (2019) के तहत स्थानीय शिकायत समितियों की स्थिति और कार्यप्रणाली पर एनएचआरसी की रिपोर्ट देखें।//एन. आर. सी.ठीक है।यौन उत्पीड़न के तहत स्थानीय शिकायत समितियों की स्थिति और कार्य।पी. डी. एफ. (17.10.2023 पर पहुँचा)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

17. इस तरह, अधिनियम पीड़ित महिला और प्रतिवादी दोनों के लिए एक व्यापक गुंजाइश पर विचार करता है, और यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम, निषेध और निवारण सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं या एल. सी. पर एक सार्वजनिक कर्तव्य रखता है। एल. सी. का संचालन और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करना, इन उपायों को असंगठित क्षेत्र के लिए सुलभ बनाने की कुंजी है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगे गए विशिष्ट सी निर्देशों पर चर्चा

18. वर्तमान रिट याचिका में जिन निर्देशों के लिए अनुरोध किया गया है, उनका पता सीधे इस अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों में निर्धारित दायित्वों और कर्तव्यों से लगाया जा सकता है:

| प्रार्थना | अधिनियम के तहत प्रावधान                                                        | प्रभारी सार्वजनिक पदाधिकारी/दायित्व                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| (अ)       | पॉश अधिनियम और नियमों के प्रावधानों को लागू करें।                              | -<br>यूनि ऑन ऑफ इंडिया ए, एस. टी. ने सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को खाय़ा |
| (ख)       | जिला अधिकारियों की नियुक्ति न करें                                             | खंड 5<br>राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें                               |
| ((ग)      | प्रत्येक जिले में एल. सी. नियुक्त करना                                         | धारा 6 और 7<br>जिला कार्यालय                                                   |
| ((घ)      | ए पी पी ओ एन टी एन जी नोडल अधिकारी                                             | धारा 6 (2)<br>जिला कार्यालय                                                    |
| (ई)       | सी. सी. सी. एस. एन. एल. कार्यस्थलों को एस के तहत परिभाषित किया गया है।<br>2(ओ) | खंड 4<br>प्रत्येक नियोक्ता द्वारा गठित किया जाना                               |

|     |                                                         |               |              |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| (च) | सभी कार्यस्थलों से रिपोर्टिंग और संग्रह सुनिश्चित करें। | धारा 21 और 22 | जिला अधिकारी |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|

शामिल करने के लिए पहल फाउंडेशन और ए. एन. आर. v. भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 694

693

|       |                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (जी)  | ए. एन. यू. ए.<br>एल. सी. ओ.<br>एम. पी. एल.<br>आई. ए. एन.<br>सी. ई. आर.<br>ई. पी. ओ.<br>आर. टी. एस.<br>ए. आर. ई.<br>समेकित और<br>रिपोर्ट<br>सार्वजनिक<br>डोमेन में<br>प्रकाशित की<br>जाती हैं। | धारा 23                | उचित सरकार                                                                                                        |
| (ज)   | अधिनियम और<br>नियमों को<br>सार्वजनिक करना<br>अधिनियम के<br>प्रावधानों की<br>समझ                                                                                                               | धारा 4; धारा 20<br>(2) | उपयुक्त सरकार;<br>जिला अधिकारी<br>जागरूकता के<br>लिए गैर सरकारी<br>संगठनों को<br>शामिल करने के<br>लिए कदम उठाएंगे |
| ((i)) | सभी कार्यस्थलों<br>पर महत्वपूर्ण<br>प्रावधानों का सार                                                                                                                                         | धारा 19 (बी)           | प्रत्येक नियोक्ता का<br>कर्तव्य                                                                                   |
| (जे)  | प्रचलित नियमों के<br>पहलुओं को स्पष्ट<br>करने के लिए<br>नियम और निर्देश<br>तैयार करना।                                                                                                        | धारा 29                | संघ सरकार                                                                                                         |

19. प्रार्थना (छ) राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देना कि जिला अधिकारियों द्वारा एकत्र की गई वार्षिक अनुपालन रिपोर्टों को समेकित किया जाए और

रिपोर्टों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाए, इस पर कुछ विचार करने की आवश्यकता है। अधिनियम की धारा 23 इस प्रकार है:

**“23. कार्यान्वयन की निगरानी और रखरखाव के लिए उपयुक्त सरकार**

डेटा।- उपयुक्त सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के सभी मामलों के संबंध में नेतृत्व और निपटारे के मामलों की संख्या पर डेटा बनाए रखेगी।”

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

जबकि अधिनियम सार्वजनिक क्षेत्र में इस तरह के प्रकाशन पर विचार नहीं करता है, निश्चित रूप से दर्ज किए गए और निपटाए गए मामलों पर इस अनाम डेटा का उपयोग करने में योग्यता है, जो आंकड़ों को समेकित करने के लिए है, जो अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता को प्रतिबिंबित करेगा। इसलिए, जबकि इस न्यायालय द्वारा इस तरह के स्पष्ट निर्देश की कोई आवश्यकता नहीं है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, पारदर्शिता और सुशासन के हित में इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने पर विचार कर सकती है-जिसकी पहुंच निश्चित रूप से विभिन्न हितधारकों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। इससे इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी भी मजबूत होगी। 20. अधिनियम की धारा 29 में दिए गए नियमों और/या निर्देशों को तैयार करने की प्रार्थना (जे) याचिकाकर्ता द्वारा बताई गई तीन कमियों तक सीमित है: (i) आई. सी. सी. और एल. सी. से वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट एकत्र करने में जिलों की भूमिका को स्पष्ट करना; (ii) अधिनियम के गैर-अनुपालन के लिए एफ. आई. एन. एस. एकत्र करने में जिला अधिकारियों की भूमिका; और (iii) एफ. आई. एन. एस. के संग्रह के लिए उपयुक्त प्राधिकरण की पहचान करना। इस अदालत ने नियमों पर बारीकी से विचार किया है, निश्चित रूप से कुछ खामियां हैं। बिंदु (i) पर, पैराग्राफ 8 में इस अदालत की चर्चा इस स्थिति को स्पष्ट करती है-हालांकि नियमों में स्पष्ट रूप से इसे निर्धारित करने के लिए आवश्यक संशोधन उचित होगा। बिंदु (ii) और (iii) वास्तविक चिंता का कारण हैं।

21. अधिनियम की धारा 26 (1) नियोक्ता पर निम्नलिखित कार्यों में विफल रहने के लिए जुर्माना लगाएगी: धारा 4 के तहत आई. सी. सी. का गठन करना, धारा 13 और 14 के तहत पूछताछ करना, धारा 22 के अनुसार वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना, या अधिनियम या नियमों के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करना। अधिनियम के उल्लंघन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, नियम वास्तव में गैर-अनुपालन पर ध्यान देने के लिए जिम्मेदार रिपोर्टिंग प्राधिकरण और उक्त संख्या 27 को एकत्र करने के लिए सशक्त सार्वजनिक प्राधिकरण पर दुखद रूप से चुप हैं। अधिनियम की योजना को देखते हुए, यह सिफारिश की जाएगी कि

27 अन्य प्रावधान जो दंड पर विचार करता है, वह धारा 17 [शिकायत और जांच कार्यवाही की सामग्री को प्रकाशित करने या ज्ञात करने के लिए दंड] है जिसमें कहा गया है:

“17. जहां इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जाने वाली शिकायत, जांच या किसी भी सिफारिश या कार्रवाई को संभालने या उससे निपटने का कर्तव्य सौंपा गया कोई भी व्यक्ति धारा 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह उक्त व्यक्ति पर लागू सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार या जहां ऐसा कोई सेवा नियम मौजूद नहीं है, उस तरीके से दंड के लिए उत्तरदायी होगा जो निर्धारित किया जाए।”

पी. ओ. एस. एच. नियमों के नियम 12 ने शुल्क रुपये निर्धारित किया है। 5000, जो नियोक्ता द्वारा एकत्र किया जाना है।

शामिल करने के लिए पहल फाउंडेशन और ए. एन. आर. v. भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 696

695

जिला कार्यालय को ही यह प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए-हालाँकि, वर्तमान में चूंकि वे अधिनियम का पालन न करने के लिए नियोक्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए सशक्त नहीं हैं, इसलिए यह ढाँचे को दाँतहीन बना देता है। इसी तरह धारा 26 (2) के तहत जो एक ही प्रावधानों के निरंतर उल्लंघन के लिए एक नियोक्ता पर और जुर्माना (व्यापार लाइसेंस को रद्द करने या नवीनीकरण को वापस लेने या सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उनके व्यवसाय/गतिविधि को जारी रखने के लिए आवश्यक पंजीकरण को रद्द करने की मंजूरी सहित) प्रदान करता है-इस कार्य को करने के लिए जिम्मेदार अधिनियम के तहत प्राधिकरण का उल्लेख नहीं करता है।

निष्कर्ष और निर्देश

22. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के लिए पॉश अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और इसे व्यवहार्य बनाने के लिए निम्नलिखित निर्देश (संबंधित शीर्षों के तहत) जारी करना उचित है:

केंद्र सरकार और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के बीच समन्वय

आई. प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के महिला और बाल विकास मंत्रालय को अपने प्रधान सचिव के माध्यम से विभाग के भीतर एक 'नोडल व्यक्ति' की पहचान करने पर विचार करना चाहिए, जो पॉश अधिनियम के तहत विचार किए गए समन्वय की देखरेख और सहायता कर सके। यह व्यक्ति इस अधिनियम और इसके कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार के साथ समन्वय करने में भी सक्षम होगा।

ii. प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार को 8 सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार को निम्नलिखित निर्देशों के अनुपालन की एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। उत्तराखंड को विभिन्न रिपोर्टों को समेकित करने, राज्य द्वारा अनुपालन में किसी भी चूक की पहचान करने और इसे सुधारने का प्रयास करने का निर्देश दिया जाता है, इससे पहले कि राज्यों के अनुपालन और इस निर्णय की तारीख से 12 सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार द्वारा निर्देश के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण दिया जाए।

**B. सार्वजनिक प्राधिकरणों की नियुक्ति**

iii.राज्य/केंद्र शासित प्रदेश महिला और बाल मंत्रालय के संबंधित प्रधान सचिव [या कोई अन्य विभाग, नीचे दिए गए निर्देश (vii) के अनुसार नियमों में संशोधन के अधीन] व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

इस निर्णय की तारीख से चार सप्ताह के भीतर धारा 5 के तहत उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रत्येक जिले में एक जिला अधिकारी की नियुक्ति।

iv.इसके बाद, प्रत्येक नियुक्त जिला अधिकारी

(क) धारा 6 (2) के अनुपालन में ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र के प्रत्येक प्रखंड, तालुका और तहसील और शहरी क्षेत्र के वार्ड या नगरपालिका में नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए;

(ख) अधिनियम की धारा 6 और 7 के तहत एक एल. सी. का गठन करना चाहिए; और

(ग) यह सुनिश्चित करें कि इन नोडल अधिकारियों और एल. सी. के संपर्क विवरण को इस फैसले की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के भीतर नोडल व्यक्ति को भेज दिया जाएगा।

इसके बाद, इस निर्णय की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर, सभी जिला अधिकारियों के नाम और उनके संपर्क विवरण (फोन, पता और ईमेल) के साथ-साथ विभिन्न नोडल अधिकारियों के जिलेवार चार्ट और उनके संपर्क विवरण वाला एक परिपत्र/बुलेटिन, विभाग की वेबसाइट पर (या एक के अभाव में, मुख्य राज्य सरकार की वेबसाइट पर) एक विशिष्ट स्थान पर, अधिनियम, नियमों के एक संकलित संस्करण और अधिनियम की मूल बातों पर सरल चार्ट/व्याख्याकर्ताओं के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।

ग. उन नियमों में संशोधन और अंतराल जिन्हें राज्य को पूरा करना होगा

vi.केंद्र सरकार को नियमों में संशोधन करने पर विचार करना चाहिए, ताकि एक रिपोर्टिंग प्राधिकरण और/या एक वित्तीय संग्रह प्राधिकरण को मान्यता देकर अधिनियम की धारा 26 को लागू किया जा सके।इस निर्देश को उपरोक्त पैराग्राफ 8 (वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के संबंध में जिला अधिकारियों की भूमिका) और पैराग्राफ 21 (अधिनियम में विचार की गई दंड व्यवस्था और नियमों में परिणामी खामियों पर) में चर्चा के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए।

vii.केंद्र सरकार नियमों में संशोधन करने पर भी विचार कर सकती है ताकि एक विभाग (अधिमानतः महिला और बाल विभाग) की पहचान की जा सके और उक्त विभाग के भीतर एक 'नोडल व्यक्ति' पद बनाया जा सके जो 697 में आवश्यक समन्वय के लिए जिम्मेदार हो।

शामिल करने के लिए पहल फाउंडेशन और ए. एन. आर. v. भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 698

अधिनियम का कार्यान्वयन [निर्देश (i) देखें]। इससे देश भर में अधिनियम के कार्यान्वयन में अधिक एकरूपता सुनिश्चित होगी।

#### **D. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण**

viii. जिला अधिकारियों और एल. सी. को उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के बारे में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अधिनियम में विचार किए गए निवारण ढांचे में उनकी स्थिति को देखते हुए, उन्हें पहले यौन उत्पीड़न की प्रकृति, कार्यस्थल में होने वाली लैंगिक बातचीत आदि के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। राज्य सरकारों को जिला स्तर पर आवधिक और नियमित प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना चाहिए जिसमें जिला अधिकारी, एल. सी. के सदस्य और नोडल अधिकारी भाग लेते हैं। [धारा 24 (बी)]।

#### **ई. जागरूकता की दिशा में बड़े प्रयास**

ix. धारा 24 को आगे बढ़ाते हुए, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और केंद्र सरकार को इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने के लिए शैक्षिक, संचार और प्रशिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए आवंटित और या आवश्यक वित्तीय संसाधनों को निर्धारित करें और उपरोक्त दिशा (viii) में विस्तृत अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करें। यह कार्य योजना, प्रत्येक राज्य द्वारा दायर अनुपालन शपथ पत्र का हिस्सा होनी चाहिए। पैराग्राफ 16 में की गई चर्चा को इस दिशा के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

x. एक बार राज्य द्वारा नामित किए जाने के बाद जिला अधिकारियों को जिले के भीतर महिलाओं के साथ काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और उनकी सुरक्षा की पहचान करने और जागरूकता पैदा करने के लिए धारा 20 (बी) के तहत अपने कर्तव्य के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है।

xi. उपयुक्त सरकारी या जिला अधिकारियों को भी एल. सी. के अस्तित्व के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास करना चाहिए, और उन्हें असंगठित क्षेत्र के लिए सुलभ बनाना चाहिए-इस प्रकार इस अधिनियम के क्षेत्रीय आयात को चालू करना चाहिए।

#### **सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट**

[2023] 13 एस सी आर।

xii. निर्देश (iv) और (v) ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य और अन्य में पारित किए गए। 28 (उपर्युक्त) में विशेष रूप से अधिकारियों, प्रबंधन और नियोक्ताओं को आई. सी. सी. और एल. सी. के सदस्यों को उनके कर्तव्यों से परिचित कराने का निर्देश और यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त

करने पर विस्तृत चरण-वार तरीके से जांच करने का निर्देश शामिल है। अभिविन्यास कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार, जागरूकता कार्यक्रम आदि आयोजित करना और महिला कर्मचारियों और महिला समूहों को अधिनियम, नियमों और विनियमों के बारे में शिक्षित करना दोहराया जाता है। इस संबंध में अधिकारियों, प्रबंधनों, नियोक्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नालसा द्वारा तैयार किए गए मॉड्यूल (ऑरेलियानो फर्नांडीस में निर्देश (vi) के अनुसार) का उपयोग किया जा सकता है।

xiii. यहां यह जोड़ना प्रासंगिक है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने पॉश अधिनियम 29 के कार्यान्वयन के लिए एक पुस्तिका तैयार की है, जो न केवल जानकारी चाहने वाले कर्मचारियों के लिए, बल्कि विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी एक उपयोगी मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है जिन्हें आई. सी. (नियोक्ता द्वारा) या एल. सी. (जिला अधिकारी द्वारा) के सदस्यों के रूप में नामित या नियुक्त किया जाता है। एतद्द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि इस जानकारी को प्रत्येक जिला अधिकारी के साथ साझा करने के लिए एक लक्षित प्रयास किया जाए, जो इसे अपने संबंधित एल. सी., धारा 6 (2) के तहत नियुक्त नोडल अधिकारियों और अपने स्वयं के आई. सी. सी. का गठन करने वाले नियोक्ताओं को प्रसारित कर सकते हैं।

#### एफ. वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट

xiv. धारा 21 (1) और (2) और धारा 22 का राज्य के प्रत्येक जिला अधिकारी द्वारा उचित अनुपालन किया जाना चाहिए-जिसमें आई. सी./नियोक्ताओं (या जानकारी जहां कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है) और एल. सी. से रिपोर्ट एकत्र करना और राज्य के साथ साझा करने के लिए एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करना शामिल है।

28 सिविल अपील सं. 2482/2014 में दिनांकित 12.05.2023 निर्णय। आर.

29 भारत सरकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर पुस्तिका (2015) // डब्ल्यूसीडी। ठीक है।  
इन/साइट/डिफॉल्ट/फाई लेस/हैंडबुक% 20 ऑन% 20 सेक्स्युअल% 20 हैरासमेंट% 20 का% 20 महिला% 20 आ% 20 कार्यस्थल। पी. डी. एफ. (26.09.2023 पर पहुंचा)।

शामिल करने के लिए पहल फाउंडेशन और ए. एन. आर. v. भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 700

699

सरकार। राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को इस प्रक्रिया के लिए प्रक्रिया और समय-सीमा सहित एक मानक संचालन प्रक्रिया (एस. ओ. पी.) बनाने का निर्देश दिया जाता है, ताकि वे अधिनियम की धारा 23 का पालन कर सकें, यानी कार्यान्वयन की निगरानी कर सकें और आंकड़ों का रखरखाव कर सकें। इस निर्देश को उपरोक्त अनुच्छेद 18 में निहित चर्चा के आलोक में पढ़ा जा सकता है।

जी. आई. सी. की निगरानी और नियोक्ताओं द्वारा अनुपालन

xv. ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य में दिए गए निर्देश

& ओआरएस। 30 (ऊपर) सबसे विशेष रूप से, आई. सी. के गठन को संबोधित करता है-सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में [मोटे तौर पर धारा 2 (ओ) (आई) के भीतर आने वाले] और कुछ निजी प्रतिष्ठानों में-जैसे कि पेशेवर संघों को नियंत्रित करने वाले निकाय, आदि।; उन निर्देशों को एतद्द्वारा दोहराया जाता है, ताकि प्रयासों की बहुलता या ओवरलैप से बचा जा सके। हालाँकि, यह निर्देश दिया जाता है कि किए गए प्रयास अधिनियम की योजना के अनुरूप होने चाहिए, और विभिन्न भूमिकाओं के लिए इस प्रकार नामित अधिकारियों के माध्यम से होने चाहिए।

xvi. इसी तरह, अस्पतालों, नर्सिंग होम, खेल संस्थानों, स्टेडियमों, खेल परिसरों, या प्रतियोगिता या खेल स्थलों (जैसा कि धारा 2 (ओ) (iii) और (iv) में परिभाषित किया गया है) को आईसी स्थापित करने और इस अधिनियम के तहत कर्तव्यों के अनुसार अनुपालन की रिपोर्ट करने के निर्देश दिए जाते हैं।

xvii. जिला अधिकारी को धारा 2 (ओ) के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों द्वारा संकलित) की एक सूची प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे उन्हें लिख सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि वे नियोक्ताओं से संबंधित प्रावधानों और उनके कर्तव्यों (धारा 4 के तहत आई. सी. सी. के गठन, धारा 19 के तहत कर्तव्यों आदि सहित) से अच्छी तरह वाकिफ हैं और उन्हें अक्षरशः लागू कर रहे हैं। यह धारा 21 के तहत वार्षिक रिपोर्टों के संग्रह को भी सक्षम बनाएगा। धारा 2 (ओ) (ii) के तहत सभी निजी क्षेत्र के कार्यस्थलों को परिणामी निर्देश

30 सिविल अपील सं. 2482/2014 में दिनांकित 12.05.2023 निर्णय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

जिला अधिकारी द्वारा संस्थाओं की एक विस्तृत सूची को समझने में सक्षम होने के बाद इसे पारित किया जा सकता है।

23. आगे के अनुपालन के लिए इस मामले को फरवरी 2024 के पहले सप्ताह में सूचीबद्ध करें।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

निर्देश जारी किए गए।

अंकित ज्ञान